www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 139 | जौनपुर शनिवार, 03 जनवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

केरल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को मिला जोरदार समर्थन

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर) को राजनीतिक दलों और आम जनता से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक राज्य में कुल 60,061 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को एसआईआर से संबंधित दैनिक बुलेटिन जारी किया, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का विवरण दिया गया है। यह प्रक्रिया 2,54,42,352 मतदाताओं वाली प्रारूप मतदाता सूची के आधार पर की जा रही है।दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 23 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और यह 22 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) के माध्यम से आवेदन जमा कराए हैं। इसमें छह राष्ट्रीय दलों ने भी भागीदारी की है।राष्ट्रीय दलों में सीपीआई (एम) सबसे आगे रहा, जिसने 21,246 आवेदन दिए। इसके बाद कांग्रेस ने 20,278, भाजपा ने 7,249, आम आदमी पार्टी ने 175, बहुजन समाज पार्टी ने 5 और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 9 आवेदन जमा कराए। राज्य स्तरीय दलों में सीपीआई से 5,120, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) से 4,289, जनता दल (एस) से 27, केरल कांग्रेस से 474, केरल कांग्रेस (एम) से 493 और आरएसपी से 596 आवेदन प्राप्त हुए हैं।प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले नाम जोड़ने के लिए 3.59 लाख आवेदन, जबकि 30,202 आवेदन प्रवासी मतदाताओं से प्राप्त हुए थे।

राहुल गांधी की तुलना पर संजय निरुपम का पलटवार

मुंबई, (एजेंसी)। कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान श्रीराम से किए जाने पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को बेहद बेतुका और हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के विरोध का रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाते हुए संजय निरुपम ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में वहां हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे भारत में गहरा आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस वजह से लोगों में भारी गुस्सा और नाराजगी है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गतिविधि को लेकर यह आक्रोश सामने आ सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी भारतीय हस्ती की गतिविधियों में बांग्लादेशी कनेक्शन दिखता है, तो मौजूदा माहौल में यह विवाद का कारण बन सकता है।इसके साथ ही संजय निरुपम ने ठाकरे गुट की शिवसेना (यूबीटी) पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस शिवसेना की स्थापना हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने की थी, वह हमेशा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की विचारधारा के साथ खड़ी रही।

नए साल में दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति से आपके संकल्प की सिद्धि हो : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक संदेश शेयर किया, जिसमें उन्होंने लोगों को नए साल में दृढ़ संकल्प, उद्देश्य की स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर लिखा, ष्मेरी कामना है कि आने वाले समय में आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिले। दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो।ष उन्होंने एक संस्कृति सुभाषित में शेयर करते हुए लिखा, उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं भूतिकर्मसु। भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमव्यथैः।ष उन्होंने शुक्रवार को भारत केसरी मन्नथु पद्मनाभन

की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्एक्सश पोस्ट में लिखा, ष्मन्नथु पद्मनाभन की जयंती पर, हम एक महान शख्सियत को बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह एक दूर की सोचने वाले व्यक्ति थे जो मानते थे कि सच्ची तरक्की आत्म–सम्मान, बराबरी और समाज सुधार में ही निहित है। हेल्थ, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका खास योगदान प्रेरणा देने वाला है। उनके विचार हमेशा न्याय, दया और एकता से भरे समाज बनाने की हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे।ष पिछले दो दिन में प्रधानमंत्री के संदेशों में प्रेरणादायक मार्गदर्शन के साथ–साथ सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों को शेयर किया है। इससे पहले, गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति, समृद्धि व समग्र कल्याण की कामना की।

ओम बिरला ने राजस्थान के बूंदी में 29 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में 29 करोड़ रुपये की लागत से टाउन हॉल और सड़क विकास परियोजनाओं का बृहस्पतिवार को उद्घाटन किया और जिले को पर्यटन, कृषि और उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। नगर परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कोटा–बूंदी के सांसद बिरला ने कहा कि नया साल विकास के एक नये चरण की शुरुआत करेगा, जिसमें बूंदी की समग्र प्रगति के लिए की गई विभिन्न पहलों के स्पष्ट नतीजे दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बूंदी को विकास के मामले में अग्रणी बनाना और इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन शहर के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक विकास योजना तैयार की गई है। बूंदी की पर्यटन क्षमता पर

प्रकाश डालते हुए बिरला ने कहा कि रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य जिले को पर्यावरण पर्यटन में राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलायेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कोटा–बूंदी 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद यातयात संपर्क में सुधार होगा और निवेश को आकर्षित करके औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने के लिए एक कृषि–तकनीक मेले का आयोजन किया जायेगा।

सीएम धामी ने विकास योजनाओं के लिए 160.54 करोड़ रुपए की धनराशि का दिया अनुमोदन

देहरादून, (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों की सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों के चौडीकरण एवं मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के प्रयासों में तेजी लाए जाने के साथ ही आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में संचार सुविधाओं के विकास आदि के लिए कुल 160.54 करोड़ रुपए का

अनुमोदन प्रदान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की विभिन्न 16 योजनाओं की लागत 53.68 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।सीएम धामी द्वारा जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगला–किच्छा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–44) के किमी 4.850 से किमी 12.600 तक के हिस्से को दो लेन से चार लेन में बदलने की योजना के लिए 80.63 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के लिए वन प्रभागों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों हेतु तात्कालिक रूप से 11.00 करोड़ रुपए की योजना राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किए जाने के साथ ही आपदा के दृष्टिगत संवेदनशील 5 जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर) में पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत किए जाने हेतु 15.23 करोड़ रुपए की योजना राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

सीएम योगी ने कहा सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के दिये निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटन, व्यय आदि की अद्धयावधिक प्रगति पर अधिक बजट प्राविधान वाले प्रमुख 20 विभागों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख 20 विभागों के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग समय से आवंटन बजट का इस्तेमाल करें ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूरी हो सकें और प्रदेशवासी इन

योजनाओं लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को समय से खर्च करने के लिए अधिकारी निर्णय लेने का सामर्थ्य विकसित करें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वह इसमें तेजी लाएं। साथ ही बजट को समय से खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक–एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सभी विभाग के अधिकारी तुंरत निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी से समय से बजट व्यय नहीं हो पाता है। ऐसे में निर्णय लेने में तेजी दिखाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है। इसमें तेजी लाने के लिए विभागीय मंत्री और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर हर माह बैठक करें। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिये कि जिन विभागों के आवंटन बजट के कुछ अंश को अभी तक किंहीं कारणों से जारी नहीं किया गया है, उन विभागों को तत्काल बजट आवंटित करें। उन्होंने सभी प्रमुख 20 विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों को विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी किया जाता है। इसके लिए विभाग के मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी करने के लिए पैरवी करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखें और फोन से फालोअप करें। इसको लेकर मुख्य सचिव भी पहल करें। उन्होंने अपने कार्यालय को निर्देश दिये कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है।

जेपी नड्डा ने ई-बिल प्रणाली का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मोदी सरकार के श्डिजिटल इंडियाश के विजन और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के तहत उर्वरक विभाग ने डिजिटल शासन और वित्तीय सुधारों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार(01 जनवरी) को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में ई–बिल प्रणाली का उद्घाटन किया, जिससे सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी की प्रक्रिया कर सकेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रणाली मैनुअल, कागज–आधारित प्रक्रियाओं से पूरी तरह से डिजिटल कार्यप्रवाह की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जिससे बिलों के भौतिक हस्तांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। नड्डा

ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, ष्यह ऑनलाइन सिस्टम पारदर्शी, कुशल और टेक्नोलॉजी–आधारित गवर्नेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।ष वहीं उर्वरक सचिव रजत कुमार मिश्रा ने इस लॉन्च को षविभाग के वित्तीय संचालन के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मील का पत्थरष बताया। यह पहल उर्वरक विभाग की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) और वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के बीच एक तकनीकी साझेदारी का परिणाम है। सीजीए संतोष कुमार ने कहा कि यह परिवर्तन सभी वित्तीय लेनदेन के लिए एक केंद्रीकृत और छेड़छाड़–रहित डिजिटल ऑडिट ट्रेल बनाकर पारदर्शिता और जवाबदेही को काफी हद तक बढ़ाता है, जिससे निगरानी और ऑडिट आसान हो जाते हैं। उर्वरक सब्सिडी भुगतान की समय पर होगा बता दें कि यह सिस्टम खर्चों की रियल–टाइम निगरानी और मजबूत वित्तीय नियंत्रण प्रदान करता है, जिसमें सभी भुगतानों को ट्रैक किया जाता है और केंद्रीय रूप से रिपोर्ट किया जाता है। वहीं उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनोज सेठी ने कहा कि यह सिस्टम ष्एंड–टू–एंड डिजिटल बिल प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है, जो भुगतान की समय–सीमा को काफी तेज करेगा, जिसमें साप्ताहिक उर्वरक सब्सिडी भुगतान की समय पर रिलीज भी शामिल है। यह ई–बिल प्लेटफॉर्म उर्वरक कंपनियों को ऑनलाइन क्लेम जमा करने और रियल टाइम में भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

पंजाब में `युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के 10 महीने, 42 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए ड्रग्स के खिलाफ अभियान श्युद्ध नशा विरुद्धश को 10 महीने पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने 1 मार्च, 2025 से अब तक 29,351 एफआईआर दर्ज की हैं और 42,622 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न कार्रवाइयों में 1,849 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।इस एंटी–ड्रग अभियान की शुरुआत के बाद से डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक साथ ऑपरेशन चला रही है। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा था। पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया है।1,849 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के अलावा पुलिस ने 599 किलोग्राम अफीम, 272 क्विंटल पोस्ता के छिलके, 51 किलोग्राम चरस, 624

किलोग्राम गांजा, 28 किलोग्राम आईसीई , 46 लाख नशीली गोलियांष्टैबलेट और 15.26 करोड़ रुपए ड्रग मनी भी जब्त की है।306वें दिन पंजाब पुलिस ने 49 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 468 ग्राम हेरोइन, 202 नशीली गोलियां और 2,500 रुपए ड्रग मनी बरामद की। उन्होंने बताया कि 61 राजपत्रित अधिकारियों की देखरेख में 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों वाली 100 से ज्यादा टीमों ने राज्यभर में 257 जगहों पर छापे मारे, जिससे राज्यभर में 38 एफआईआर दर्ज की गईं।

अरुणाचल की महिला के चीन में उत्पीड़न के मुद्दे पर भड़के जयशंकर

चेन्नई, (एजेंसी)। बीते नवंबर में अरुणाचल प्रदेश की एक महिला ने चीन पर आरोप लगाया था कि भारतीय पासपोर्ट होने के चलते उनका चीन के हवाई अड्डे पर उत्पीड़न किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि चीन के आव्रजन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को मानने से ही इनकार कर दिया था। अब इसे मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अपनी बात रखी। उन्होंने इसे चीन की चालबाजी करार दिया

और सख्त लहजे में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश की महिला को कथित तौर पर चीन के आव्रजन अधिकारियों द्वारा शंघाई हवाई अड्डे पर उत्पीड़न किए जाने को लेकर सवाल किया गया। इस पर जयशंकर ने कहा, श्अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इस तरह की चालबाजियों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। जयशंकर ने कहा, श्हमने इस मुद्दे पर चीन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया था। साथ ही हमने साफ कह दिया कि इस तरह की चीजें करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा है और लोगों को आवागमन के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम, कायदे–कानून हैं और हम चाहते हैं कि देश इनका सम्मान करें। हमारा इस मुद्दे पर दृढ़ रुख रहा। कार्यक्रम के दौरान डॉ. जयशंकर से भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, श्आपके पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो पता चलता है कि दुर्भाग्य से हमारे साथ भी ऐसा है।

चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार में फ्रॉड भरे पड़े हैं : सुप्रिया श्रीनेत

नई दिल्ली, (एजेंसी)।देश के लोकतंत्र में म्टड और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर छिड़ी बहस अब एक नए मोड़ पर आ गई है। अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड में लीड स्टोरी छपी है। जिसमें बताया गया है कि हाल ही में एक सर्वे करवाया गया जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि देश के अधिकांश नागरिकों को ईवीएम पर पूरा भरोसा है और वो मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग के इस ताजा सर्वे पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इस सर्वे की श्क्रोनोलॉजीश और इसके पीछे के किरदारों को देखें, तो दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने ये सर्वे से करवाया है.. अब सवाल ये उठता है कि ये एनजीओ किसका है और क्या ये एनजीओ वाकई स्वतंत्र है? दरअसल इस एनजीओ के संस्थापक डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम न सिर्फ च्डट में कार्यरत

हैं, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुर समर्थक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व पर पावर विदिन नाम की किताब भी लिखी। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की संस्था से निष्पक्ष सर्वे की उम्मीद करना, जो खुद सरकार का हिस्सा हो, हास्यास्पद लगता है।इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा –चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने श्वोट चोरीश में खुद को क्लीन चिट देने के लिए एक सर्वे कराया। इस सर्वे में बताया गया कि जनका को म्टड पर भरोसा है और लोग मानते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं..रोचक बात है ये सर्वे जिस ने किया, वह नरेंद्र मोदी के करीबी आर. बाला सुब्रमण्यम का है। इतना ही नहीं। बालासुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी की चापलूसी में किताब भी लिखी है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि उनका वोट चोरी का खेल जनता के सामने आ गया है। इसलिए अपने करीबियों से ऐसे फर्जी सर्वे करा कर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता श्वोट चोरीश का सच जान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, इस तरह के फर्जी सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आपकी घबराहट ही नजर आती है।इस पूरे मामले में सबसे बड़ा पेंच टाइमिंग का माना जा रहा है..जैसा कि कांग्रेस ने बताया.. कि ये सर्वे मई 2025 में करवाया गया था. और राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का बड़ा खुलासा अगस्त 2025 में किया.।

संपादकीय

नियम-कानून की कोई परवाह नहीं

नेशनल हेराल्ड मामले में वैध एफआईआर ही मौजूद नहीं है। क्या ईडी के अधिकारियों को कानून की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो वे नियम– कानून की कोई परवाह नहीं करते? नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को राहत मिली, मीडिया की सुर्खियों में इसी पहलू को अहमियत दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसका यह सिर्फ एक पक्ष है। लेकिन यह मूल बात नहीं है। कांग्रेस नेताओं को राहत इसलिए मिली, क्योंकि जज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संज्ञान इसलिए नहीं लिया, क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मामले की एफआईआर ही वैध ढंग से दर्ज नहीं हुई है। हुआ यह कि एक व्यक्ति (भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी) ने निजी तौर पर एफआरआर दर्ज कराई। उसमें कांग्रेस नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए। ईडी ने उसी मामले में जारी समन के आधार पर केस अपने हाथ में लेकर में जांच शुरू कर दी। यानी उसने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। जज विशाल गोगने ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून की संबंधित धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ईडी निजी एफआईआर के आधार पर चार्जशीट तैयार नहीं कर सकती। जज का यही वो निष्कर्ष है, जो ईडी की कार्यशैली को बेनकाब कहता है। सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को कानूनी धाराओं की इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है? या जब मामला विपक्षी नेताओं से संबंधित हो, तो अपने सियासी आकाओं के इशारे पर वे नियम– कानून की कोई परवाह नहीं करते? सत्ताधारी भाजपा और उसके समर्थक नेटवर्क ने वर्षों से नेशनल हेराल्ड मामले को गांधी परिवार के कथित भ्रष्टाचार की मिसाल बता कर प्रचारित किया है। मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ हुई। मगर अब सामने आया है कि यह सब उस मामले में हुआ, जिसमें एफआईआर ही वैध नहीं थी। सामान्य स्थितियों में कायदे का इस रूप में उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाती, ताकि भविष्य में अधिकार के ऐसे दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी उम्मीद करना बेमतलब है। अभी तो संभावना यही है कि ऊपरी अदालत में अपील की आड़ में सारा मामला पृष्ठभूमि में डाल दिया जाएगा।

अस्तित्व संकट के बीच पारिवारिक एकता का राग

उमेश

राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहां कोई न तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। राजनीति में ऐसे कम ही उदाहरण मिलेंगे,जहां दोस्ती के मूल में दिल का रिश्ता होता है। गौर से देखें तो संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों की बुनियाद पर पर दोस्ती या दुश्मनी के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के दो राजनीतिक परिवारों के मिलन को भी इसी अंदाज और संदर्भ में देखा जाना चाहिए। राज्य का पवार परिवार हो या फिर ठाकरे कुनबा, अगर एक होता नजर आ रहा है या एक हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों परिवारों के प्रमुख अलंबरदारों के दिल मिल चुके हैं। बल्कि राजनीतिक संभावनाओं और अवसरों ने उन्हें एक होने को प्रेरित किया है। चाहे ठाकरे परिवार हो या फिर पवार कुनबा, दोनों में कुछ समानताएं हैं। शरद पवार हों या बाल ठाकरे, एक दौर में दोनों की महाराष्ट्र की राजनीति में तूती बोलती थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में तो राजनीतिक हलके का एक बड़ा हिस्सा शरद पवार को देश का भावी प्रधानमंत्री तक मानने लगा था। इसी तरह महाराष्ट्र के टाइगर के रूप में बाल ठाकरे की ख्याति रही। दोनों ही राजनीतिक खानदानों के मुखिया का स्वाभाविक उत्तराधिकारी दोनों के भतीजे ही माने जाते थे। एक दौर तक शरद के उत्तराधिकारी के तौर पर देश और प्रदेश अजित पवार को देखता था। इसी तरह शिवसैनिक भी बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को अगली पीढ़ी का ठाकरे सीनियर मान चुका था। लेकिन जब उत्तराधिकार सौंपने की बारी आई तो पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर भरोसा जताया और बाल ठाकरे ने अपने छोटे बेटे राज ठाकरे को। ऐसे हालात में अजित और राज ठाकरे को अपना भविष्य चुनौतीपूर्ण लगा, राजनीतिक संभावनाएं कम होती दिखीं तो दोनों ने अपनी राह अलग कर ली। उन्नीस साल पहले राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली तो अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के मूल धड़े पर ही कब्जा कर लिया। पार्टी के असल संस्थापक शरद पवार पुछल्ला पार्टी लेकर एक तरह से किनारे का दल संभालने लगे। पवार परिवार और ठाकरे कुनबे में बिखराव की कहानी भी अलग–अलग रही। जब तक बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बीजेपी के साथ खड़ा रखे, तब तक तो उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं मिली। दल का राज्य में ठीकठाक समर्थन भी रहा। हालांकि महत्वाकांक्षाओं के साथ अलग हुए राज ठाकरे को राजनीतिक सफलताएं न के बराबर मिलीं। लेकिन जब से उद्धव ने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस और पवार की एनसीपी का साथ पकड़ा, राजनीतिक मैदान में उसका आधार घटने लगा। वहीं पवार सीनियर से अलग होने के बावजूद बीजेपी के साथ के चलते अजित का राजनीतिक रूतबा कम नहीं हुआ। अलबत्ता कभी भारत के प्रधानमंत्री मैटेरियल देखे जाते रहे वरिष्ठ पवार की सियासी साख घटती चली गई। कुनबे में बिखराव के चलते दोनों परिवारों की राजनीतिक ताकत बीजेपी के सामने बौनी होती जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों परिवारों के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा है। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। राजनीतिक अस्तित्व पर जब बन आती है तो कम ही सियासी हस्तियां होती हैं, जो समझौते नहीं करतीं। इसे समझदारी कहें या फिर राजनीति की रवायत, ठाकरे परिवार और पवार कुनबा–दोनों ही एक होने जा रहे हैं। पारिवारिक बिखराव को समेटने की कोशिश तेज हो गई है। ठाकरे बंधु तो बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस करके एक हो चुके हैं, जबकि पवार परिवार अपने गढ़ बारामती में एक होने का संकेत दे रहा है। बारामती में हाल ही में पवार परिवार ने एक आयोजन किया, जिसमें आज के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसे पवार कुनबे ने खूब प्रचारित किया। इस प्रचार का संदेश साफ है कि दोनों परिवार एक होने जा रहे हैं। चाहे ठाकरे कुनबा हो या फिर पवार परिवार, अगर दोनों एक हो रहे हैं तो उसकी सिर्फ अस्तित्व की रक्षा भी नहीं है, बीजेपी रूपी चुनौती से पार पाना भी है और मुंबई महानगर पालिका, पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जे की चाहत भी है। मुंबई महानगर पालिका का सालाना बजट सत्तर हजार करोड़ रूपए का है। यह रकम उत्तर पूर्व के राज्यों के समूचे बजट से भी ज्यादा बैठती है। पिंपरी–चिंचवड़ महानगर पालिका के दायरे में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। जाहिर है कि यहां से कर के रूप में मोटी रकम आती है। ठाकरे परिवार की एकता के पीछे एक कारण जहां बृहन्नमुंबई महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है, वहीं पवार परिवार की एकता के पीछे पुणे महानगरपालिका और पिंपरी–चिंचवड़ महानगर पालिका पर कब्जा जमाना है। दोनों परिवारों को लगता है कि अगर वे बिखरे रहे तो उनके प्रभाव वाली महानगर

पालिकाओं में उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि एक दौर में बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहता था तो पुणे और पिंपरी–चिंचवड़ में पवार परिवार का। दोनों परिवारों के मिलन के पीछे की बड़ी वजह यही है।

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, अपने विस्तार के पहले चरण में वह अपने साथी दलों के सहयोग पर निर्भर रही। बाद के दौर में उसने खुद का प्रभाव बढ़ाया और अपने दम पर वह स्थापित होती चली गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद अब इसी तरह वह महाराष्ट्र में वह अपने दम पर उभर चुकी है। जबकि कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र में एक तरह से शिवसेना के छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। अब चाहे शिवसेना का टूटा हुआ धड़ा हो या अजित पवार वाली एनसीपी, दोनों उसके छोटे भाई की भूमिका में हैं। जिस तरह निकाय चुनावों में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया है, उससे पवार परिवार की भी चिंताएं बढ़ी हैं और ठाकरे खानदान की भी। इसीलिए दोनों परिवार एक हुए हैं या होते नजर आ रहे हैं। पवार परिवार अब एक साथ पुणे और पिंपरी–चिंचवड़ के चुनाव में उतरने जा रहा है तो ठाकरे परिवार मुंबई में। लेकिन यह तय है कि दोनों परिवारों के रिश्तों की मजबूती इन महापालिका चुनाव नतीजों पर निर्भर करेगी। अगर उन्हें जीत मिली तो तय है कि पारिवारिक गठबंधन आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो दोस्ती की नई राह तलाशने की कोशिशें फिर से तेज होंगी।

टीएमसी स्थापना दिवस पर ममता बनर्जी के संदेश में दिखी निराशा ने उनकी कमजोर स्थिति उजागर की

नीरज

तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इस बार पार्टी का रुख आत्मविश्वास से भरा दिखने की बजाय आत्मरक्षा करता हुआ ज्यादा नजर आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दुष्ट ताकतों के आगे नहीं झुकने का संकल्प तो दोहराया, लेकिन उनके शब्दों की तीव्रता के पीछे छिपी चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। मां माटी मानुष के नारे के साथ शुरू हुई यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए ममता ने जनता के प्रेम और आशीर्वाद की बात कही, पर जमीन पर बदलते राजनीतिक हालात ने उनकी पार्टी के हर्षोल्लास की चमक को फीका कर दिया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पार्टी को लोकतांत्रिक ताकत बताने और बंगाल विरोधी शक्तियों से लड़ने की बातें दोहराई गईं। परंतु यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार, हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों ने तृणमूल की साख को गहरा आघात पहुंचाया है। स्थापना दिवस का भाषण भविष्य की रणनीति कम और बीते गौरव की याद अधिक प्रतीत हुआ। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा चुनावी अभियान का शंखनाद था। शाह ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर तृणमूल सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने न केवल आरोप लगाए, बल्कि 2026 के चुनाव के लिए संगठन को स्पष्ट लक्ष्य और कार्ययोजना भी सौंपी। शाह की यात्रा का सबसे अहम संकेत यह रहा कि भाजपा ने अब बंगाल में संगठनात्मक ढांचे को कसना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय, जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद, बंद कमरे की बैठकों में स्पष्ट निर्देश और पुराने नेताओं को फिर से सक्रिय भूमिका देना दर्शाता है कि भाजपा इस बार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस चुकी है। साथ ही दिलीप घोष को दोबारा आगे लाना पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश है। हम आपको बता दें कि अमित शाह ने ममता सरकार पर राज्य की जनसांख्यिकी बदलने, सिंडिकेट राज चलाने और उद्योगों को भगाने के आरोप लगाए। उन्होंने यह दावा भी किया कि बंगाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है और अब बदलाव अपरिहार्य है। भाजपा ने दो तिहाई बहुमत का दावा कर राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सप्ताह में चार दिन क्षेत्र में रहने और रोज नुक्कड़ सभाएं करने का निर्देश इस बात का प्रमाण है कि भाजपा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। बंगाल में साफ दिख रहा है कि एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने संकल्प दोहरा रही है, वहीं भाजपा सड़क पर उतरकर रणनीति को अमल में लाने में जुट गई है। यही अंतर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता नजर आ रहा है।

देखा जाये तो पश्चिम बंगाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस आज सत्ता की थकान और आत्मसंतोष की शिकार दिख रही है। स्थापना दिवस के भाषणों में संघर्ष की बातें जरूर हैं, लेकिन उन शब्दों में वह धार नहीं दिखती जो कभी ममता बनर्जी की पहचान हुआ करती थी। दुष्ट ताकतों का जिक्र दरअसल अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने का प्रयास अधिक लगता है। लंबे समय तक सत्ता में रहने का बोझ अब तृणमूल पर साफ दिखने लगा है। भ्रष्टाचार के मामलों, संगठनात्मक ढीलापन, जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष और जनता के रोजमर्रा के सवालों से कटाव ने पार्टी को रक्षात्मक बना दिया है। मां माटी मानुष का नारा आज भी दोहराया जा रहा है, लेकिन मानुष के मन में उठ रहे सवालों के ठोस जवाब तृणमूल के पास नहीं दिखते। इसके विपरीत भाजपा आक्रामक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर चुकी है। अमित शाह की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी घुसपैठ, सुरक्षा, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों को एक साथ जोड़कर तृणमूल कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। साथ ही संगठन को मजबूत करने पर जोर और अनुशासनात्मक निर्देश यह बताते हैं कि भाजपा ने पिछली गलतियों से सीख ली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने बंगाल में वैचारिक और संगठनात्मक दोनों स्तरों पर लड़ाई की तैयारी कर ली है। संघ के साथ तालमेल और पुराने चेहरों की वापसी यह संकेत देती है कि पार्टी अंदरूनी मतभेदों को पीछे छोड़कर एकजुट मोर्चा बनाना चाहती है। यह एक ऐसी रणनीति है जो तृणमूल के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। देखा जाये तो राजनीति में भावनात्मक भाषण तभी असर करते हैं जब उनके साथ ठोस काम और भरोसेमंद नेतृत्व हो। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस शब्दों के सहारे आत्मबल बढ़ाने की कोशिश में दिख रही है, जबकि भाजपा जमीन पर संगठन और मुद्दों के सहारे बढ़त बनाती नजर आ रही है। आने वाले महीनों में यदि तृणमूल ने आत्ममंथन नहीं किया और केवल विरोधियों को दोष देने की राजनीति जारी रखी, तो सत्ता की जमीन उसके पैरों से खिसक सकती है। बहराहल, पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब केवल नारों की नहीं, बल्कि संगठन, विश्वसनीयता और भविष्य की दृष्टि की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई में फिलहाल पलड़ा भाजपा की ओर झुका हुआ दिख रहा है और तृणमूल को इस सच्चाई का सामना करना ही होगा।

उमर खालिद के समर्थन में उतर कर जोहरान मामदानी ने बड़ा खतरनाक खेल खेला है

नीरज

न्यूयार्क के मेयर जोहरान मामदानी की ओर से भारत में तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद को भेजे गए एक पत्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह पत्र उमर खालिद के माता पिता से मुलाकात के दौरान दिया गया और इसमें मामदानी ने खालिद के विचारों की तारीफ करते हुए लिखा कि वे उनके बारे में सोच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उमर खालिद पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े गंभीर आरोपों की सुनवाई चल रही है। इस पत्र के सामने आने के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। आलोचकों का कहना है कि किसी विदेशी शहर के मेयर द्वारा भारत के एक संवेदनशील कानूनी मामले में पक्ष लेना अनुचित है। खासकर तब, जब मामला दंगों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। हम आपको याद दिला दें कि उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत आरोप हैं और वह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। ऐसे में किसी विदेशी जनप्रतिनिधि की ओर से सहानुभूति और प्रशंसा का सार्वजनिक संकेत कई सवाल खड़े करता है। हम आपको बता दें कि मामदानी के पत्र को सिर्फ एक व्यक्तिगत संदेश नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में भी इस कदम को असहज माना गया है। भारत में यह तर्क उभरा है कि यदि हर देश का स्थानीय नेता दूसरे देश के न्यायिक मामलों पर टिप्पणी करने लगे तो संप्रभुता और संस्थागत सम्मान पर आंच आएगी। देखा जाये तो जोहरान मामदानी का यह कदम साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। सवाल सीधा है। सवाल उठता है कि न्यूयार्क के मेयर को यह अधिकार किसने दिया कि वह भारत के दंगों से जुड़े एक आरोपी की तारीफ करे और उसे नैतिक समर्थन दे। मामदानी को समझना होगा कि भारत की न्याय व्यवस्था सक्षम है, संवैधानिक है और अपने फैसले खुद लेने में समर्थ है। उमर खालिद कोई साधारण सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि उस पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। ऐसे व्यक्ति को वैश्विक मंच से नैतिक समर्थन देना न केवल भारत के लिए गलत है, बल्कि यह एक खतरनाक परंपरा को जन्म देता है। इससे यह संदेश जाता है कि दंगों और हिंसा से जुड़े आरोपों को वैचारिक खोल पहनाकर महिमामंडित किया जा सकता है। यह संदेश उन तत्वों के लिए संजीवनी का काम करता है जो अराजकता और टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। मामदानी को यह समझना चाहिए था कि भारत का आंतरिक कानून और व्यवस्था किसी विदेशी राजनेता की राय का मोहताज नहीं। यदि उन्हें मानवाधिकार की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें अपने देश में चल रही हिंसा, नस्लीय तनाव और अपराध की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारत में न्याय की प्रक्रिया अदालतों के माध्यम से चलती है, न कि सोशल संदेशों और पत्रों के जरिये। इस तरह का समर्थन सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी गलत असर डाल सकता है। जब वहां के नेता दंगों के आरोपी की तारीफ करते हैं, तो यह वहां मौजूद कट्टर और हिंसक विचारधारा के लोगों का हौसला बढ़ाता है। वे इसे यह कहकर पेश कर सकते हैं कि उनके विचारों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। लोकतंत्र का अर्थ कानून का शासन है, न कि आरोपियों का महिमामंडन। यह भी याद रखना जरूरी है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र की बुनियाद एक दूसरे की संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब कोई विदेशी नेता भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है या एक पक्ष को नैतिक ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करता है, तो यह आपसी विश्वास को चोट पहुंचाता है। यह न तो कूटनीतिक मर्यादा के अनुरूप है और न ही जिम्मेदार राजनीति का उदाहरण। मामदानी का पत्र उन तमाम भारतीय नागरिकों की भावनाओं का भी अपमान है जिन्होंने दिल्ली दंगों में अपने परिजन खोए, जिनकी दुकाने जलीं और जिनका जीवन तबाह हुआ। उनके लिए दंगे कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। ऐसे में दंगों के मास्टरमाइंड की तारीफ करना घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत को किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि वह लोकतांत्रिक है या न्यायप्रिय। यहां की अदालतें स्वतंत्र हैं और फैसले सबूतों के आधार पर होते हैं। यदि उमर खालिद निर्दोष है, तो वह अदालत से बरी होगा। यदि दोषी है, तो सजा पाएगा। इसमें किसी विदेशी मेयर के भावनात्मक पत्र की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जोहरान मामदानी का यह कदम गैर जिम्मेदार, दखल देने वाला और भड़काऊ है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए।

भारत में अंग्रेजी राज ही बेहतर था!

शंकर शरण

पिछले पचास वर्षों से देसी भारतीय नेताओं के पास केवल दलीय लड़ाई, गद्दी छीन–झपट की तिकड़में भर हैं। एक–दूसरे के प्रति द्वेष, झूठे–सच्चे आरोपों की पोटली है। उसी से लोगों को उकसाना और वोट–बटोरन मंसूबे ही उन की फुलटाइम चिन्ता दिखती है।ज् नेताओं का परनिंदक, शेखीबाज, और अतीतजीवी होना हिन्दू समाज की असमर्थता का संकेत है। एक तरफ आए दिन मैकॉले, कोलोनियलिज्म, आदि की निन्दा। दूसरी तरफ भारत विश्वगुरू था, वेदों में आधुनिक साइंस की बातें हैं, आदि। इस तरह की बातों का प्रचार, व्याख्यान, प्रकाशन देश में फैला हुआ है। दोनों प्रवृत्तियों में एक चीज समान है कृ पीछे देखना। जिस का मतलब सामने की चुनौतियों से कन्नी कटाना भी हो जाता है। यह आधुनिक भारत का सामान्य दृश्य है। दोनों प्रवृत्तियाँ देसी नेताओं की देन हैं, जो अब राष्ट्रीय विशेषता सी बन गई है। आम हिन्दू नेता पीछे देखने वाले रहे हैं। अतीतजीवी हैं। प्रायरू अप्रासंगिक, अतिरंजित बातें करते। किसी न किसी को कोसना, नीचा बताना, या डींग हाँकना। इस के लिए उदाहरण व या बहाने प्रायरू सदियों, दशकों पहले के व्यक्तियों, घटनाओं, परिघटनाओं से लेना। अर्थात उन के पास भविष्य तो दूर, वर्तमान की भी दृष्टि नहीं है। ऊपर से आराम पसंद। कोसने, निन्दा करने में भी किसी वर्तमान दुष्ट या खतरनाक शत्रु पर चुप्पी। सुरक्षित निशाने चुननारू जैसे मैकॉले या नेहरू। इसीलिए, उन्हें संसद में किसी वर्तमान समस्या, दुष्ट, या प्रत्यक्ष खतरे पर चर्चा करते नहीं पाया जाता। वे प्रायरू किसी निरापद प्रतिद्वंद्वी नेता, दल, या किसी दिवंगत विदेशी को कोसते मिलते हैं। इसी तरह, कोलोनियलिज्म को कोसना भी विचित्र है! हर साल हजारों युवा प्रतिभाओं के विदेश चले जाने, और प्रायरू उधर ही बस जाने पर वे ध्यान तक नहीं देते। उन्हें योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देश में रखने, प्रोत्साहित करने की परवाह नहीं। उलटे ऐसे श्भारतवंशियोंश्च पर गर्व करते हैं जो बाहर अमेरिकी कंपनियों में अच्छे पदों पर हैं। तब उन्हें ध्यान नहीं आता कि यह श्उपलब्धिश्च यहाँ मैकॉले नीति की देन है। उपनिवेशवाद को कोसने वाले इस से अबोध लगते हैं कि अमेरिका, यूरोप, अरब जाकर रहने वाले लाखों भारतीय स्वेच्छा से विदेशी शासन में रहने जाते हैं! जहाँ वे बरसों, दशकों, या आजीवन बिना राजनीतिक अधिकार के दूसरे दर्जे के नागरिक जैसे रहते हैं। इसी पर भारतीय नेता गर्वित होते हैं! वरना, श्भारतवंशीय कर्मचारियों, शोधकर्ताओं, कारीगरों, आदि पर इतराना क्या है? तब तो भारत में अंग्रेजी राज ही बेहतर था! जब विदेशी का शासन पसंद है, यदि अपनी सुरक्षा और उन्नति का मार्ग खुला हो कृ तब यह अंग्रेजी राज ने दिया ही था। बड़े–बड़े भारतीय महापुरुषों ने लिखा है कि सदियों बाद भारतीय जनगण को अंग्रेजी राज ने शान्ति, सुरक्षा, उन्नति दी। हिन्दुओं को ऊपर से सामाजिक, राजनीतिक समानता भी मिली जो उन्हें मुगल राज में नहीं थी। परन्तु सब कुछ जोड़कर विवेकशील विचार करना कृ मानो देसी नेताओं की क्षमता से बाहर रहा है। वे रुटीन काम, दूसरों पर प्रतिक्रिया, और कठिन मुद्दों पर चुप रहते हैं। अपनी ओर से कोई रचनात्मक विचार या काम उन की चिन्ता नहीं रही है। सभी दलों के अधिकांश नेता ऐसे ही हैं। विचार–दुर्बल और पदलोलुप। चाहे पद राजकीय हो या दलीय। संसद के सत्र खँगालें, या मीडिया हेडलाइनें जमा करें कृ दशकों से यही मिलेगा। पूरे परिदृश्य में क्रमशरू गिरावट भी आती गई। देसी नेताओं द्वारा 1947 में सत्ता–ग्रहण बाद दो दशक तक स्थिति कुछ भिन्न थी। तब आर्थिक योजनाएं, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, आदि पर विचार में नेता लोग समय देते थे। इस का कारण ब्रिटिश राज की शिक्षा और परंपरा थी जिस के पास दृष्टि थी। जिस के अनुकरण और प्रतिद्वंद्विता में ही हमारे वे नेता बने जिन्होंने अंग्रेजों के बाद देसी राज शुरू किया। अतरू 1960 के दशक के अंत तक संसदीय विमर्श में जो विविधता और गंभीरता थी भी, उस का श्रेय ब्रिटिश शिक्षण–संसर्ग को है जो हमारे नेताओं को यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक मिलता रहा था। उदारवाद, संविधानवाद, स्थानीय प्रशासन, लोकतंत्र, वोट, समाजवाद तथा स्कूल से विश्वविद्यालय तक की संपूर्ण शिक्षा और अखबार तक कृ सब कुछ ब्रिटिशों से मिला था। इसलिए, 1970 के दशक से हमारे नेताओं के विचारों और आम बौद्धिक चर्चा में जो गिरावट आई, वह विशुद्ध देसी चीज है। इस में कोई भविष्य–दृष्टि, कोई मौलिकता नहीं है। इसीलिए, गत पचास सालों से देसी दृष्टि के नाम पर कोई दस्तावेज नहीं मिलता। उस के बदले केवल बदलते नारे हैं। श्समाजवाद्यश्च और श्हिन्दू राष्ट्रश्च कब का भुलाया जा चुका। श्गैर–कांग्रेसवाद्यश्च, श्इन्दिरा हटाओश्च, श्लोकतंत्र बचाओश्च, आदि भी केवल कुर्सी–कब्जे की लड़ाइयों के नाम थे। किसी में विजन नहीं था। अब तो वे नारे बनाने में भी असमर्थ हैं! जो बनते हैं, इतने खोखले कि चार साल भी नहीं टिक पाते। नेता खुद उसे चुपचाप छोड़ देते हैं। फिर जुमलों, तमाशों से काम चलाते हैं। सेल्फी, मूर्तियाँ, आदि के झुनझुने लोगों को थमाते है। यह सब वैचारिक खालीपन के ही संकेत हैं। अब किसी नेता के पास नेहरू की तरह, उधार का भी सही, कोई विचार नहीं जिस पर उन की निष्ठा हो। इसीलिए, नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, क.मा. मुंशी, लोहिया, आदि की तरह गंभीर पुस्तकें लिखना भी अब नेताओं द्वारा नहीं होता। उन में अब सुसंगत लेख लिखने लायक भी खोजने से मिलते हैं। जबकि ब्रिटिश राज में और उस के मोमेंटम में 1960 तक हर दूसरा–तीसरा बड़ा भारतीय नेता लेखक, संपादक भी हुआ करता था। उस के बाद से क्या हुआ? पिछले पचास वर्षों से देसी भारतीय नेताओं के पास केवल दलीय लड़ाई, गद्दी छीन–झपट की तिकड़में भर हैं। एक–दूसरे के प्रति द्वेष, झूठे–सच्चे आरोपों की पोटली है। उसी से लोगों को उकसाना और वोट–बटोरन मंसूबे ही उन की फुलटाइम चिन्ता दिखती है। 1970 के दशक के बाद, धीरे–धीरे श्समाजवाद्यश्च और श्गुटनिरपेक्षताश्च बेकार हो जाने पर देसी दिमाग में, देश–विदेश के बारे में, कोई सार्थक विचार नहीं आया। केवल इन्दिरा, कांग्रेस, संघ, या ब्राह्मणों की निन्दा आ गई। इस्लामी तुष्टिकरण और जातिवाद से वोट फसल काटने पर सब कुछ केंद्रित होता गया। श्हिन्दुत्वश्च का शिगूफा छोड़ने वाले खुद ही उस से भाग कर श्विकासश्च पर आ गए। सभी नारे, शिगूफे वोट की लड़ाई रहे हैं। विदेश दौरों पर भी नेता अपने प्रतिद्वंद्वी की छीछालेदर करते हैं। उन्हें देश के प्रतिनिधि होने का बोध तक भूल जाता है। तब राष्ट्रीय दृष्टि के नाम पर क्या है? वस्तुतरू देसी राज में शिक्षा, संस्कृति, और आंतरिक सुरक्षा संबंधी बिन्दु भी असल चिन्ता से दूर होते गये। फलतरू, कश्मीर, असम, पंजाब, बंगाल, बिहार, आदि की अपनी–अपनी तरह दुर्गति होती गई। उस पर चिन्ता के बदले वह भी सत्ता और विपक्ष के बीच तू–तू–मैं–मैं के हीले के सिवा कुछ खास नहीं रही। सब मिल कर किसी विषय पर रचनात्मक रूप से सोचें कृ ऐसा संसद में पिछली बार कब हुआ था? अंग्रेज शासक ब्रिटिश भारत के हित की दृष्टि से चीन, रूस, और अरब तक पर नजर रखते थे। उस की व्यवस्था करते थे, अड़ते थे। देसी शासक एक ही पीढ़ी में अधिकांश ऐसे आ गये जो अपने लोकसभा क्षेत्र से आगे देखने में असमर्थ थे! अनेक मंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र को नियामतें देकर अपना अगला चुनाव पक्का करने, तथा पार्टी आलाकमान की आरती उतारने से अधिक कुछ जरूरी नहीं समझते। देसी राज के आम नेता ऐसे हो गये, जिन्हें श्अखिल भारतीयश्च चिन्ता छू तक नहीं गई थी! यह संसद और विधानसभाओं की कार्रवाइयों का आकलन भी दिखा सकता है कि गत पचास सालों में वहाँ क्या चर्चाएं हुई, और नहीं हुई? कम्युनिज्म के विघटन, इस्लामी आतंकवाद के प्रसार, या कश्मीर से हिन्दुओं के सफाए पर कभी कोई विचार हुआ? यदि नहीं, तो इस पर किसी राष्ट्रीय नीति का अभाव रहना तय था। यह बात कितनी भी अ–देशभक्तिपूर्ण लगे, पर संपूर्ण भारत की चिन्ता अंग्रेज शासकों ने ही की। उन्होंने ही पहले इसे राजनीतिक रूप से एक किया। जो ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुआ था।

21 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव, पदोन्नति पाने वाले प्रमुख सचिव व सचिव को भी मिली तैनाती

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया है। सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाले दो और विशेष सचिव से सचिव बने कुछ अफसरों को भी नई तैनाती दी गई है। सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाली अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा से प्रमुख सचिव राजस्व और एसवीएस रंगाराव को सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद एवं निदेशक भूमि अध्यापि से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय राष्ट्रीय एकीकरण तथा सामान्य प्रशासन बनाया गया है। इसके अलावा अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव निर्वाचन से वहीं पर सचिव बना दिए गए है। नेहा शर्मा को प्रभारी महानिरीक्षक निबंधक से महानिरीक्षक निबंधक, मोनिका रानी प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा और योगेश कुमार प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक सहकारी समितियां से आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता बनाए गए हैं। डॉ. सारिका मोहन सचिव वित्त से सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, नवीन कुमार जीएस सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परियोजना प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण से सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद तथा निदेशक भूमि अध्यापि बनाए गए हैं। भवानी सिंह खंगारोत विशेष सचिव राजस्व परिषद से सचिव वित्त, अरुण प्रकाश विशेष सचिव नगर विकास से विशेष सचिव राजस्व विभाग, रविंद्र कुमार प्रथम विशेष सचिव कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से सचिव नगर विकास तथा राज्य मिशन निदेशक अमृत और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय बनाए गए हैं। दिव्य प्रकाश गिरी विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति से सचिव लोक निर्माण विभाग, कृष्ण कुमार विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परियोजना प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी, सुधा वर्मा विशेष सचिव महिला कल्याण एवं सचिव राज्य महिला आयोग से सचिव राजस्व विभाग, रेनू तिवारी सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से विशेष सचिव महिला कल्याण तथा सचिव राज्य महिला आयोग बनाई गई हैं। संजीव सिंह विशेष सचिव वित्त से निदेशक समाज कल्याण एवं प्रबंध निदेशक यूपी सिडको, डॉ. वंदना वर्मा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रबंध निदेशक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से निदेशक महिला कल्याण तथा प्रबंध निदेशक महिला कल्याण निगम बनाई गई है। उमेश प्रताप सिंह विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण को वर्तमान पद के साथ निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा प्रबंध निदेशक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कुमार प्रशांत निदेशक समाज कल्याण तथा प्रबंध निदेशक यूपी सिडको से सचिव गृह विभाग, संदीप कौर निदेशक महिला कल्याण तथा प्रबंध निदेशक महिला कल्याण निगम से सचिव वित्त विभाग बनाई गई हैं।

घने कोहरे के कारण भिड़े तीन ट्रक, दो की आमने-सामने टक्कर, तीसरा पीछे से टकराया

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेठी जिले में घने कोहरे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर असर डाला। मोहनगंज थाना क्षेत्र स्थित राजामऊ नहर पुल पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार तीन ट्रकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक खलासी समेत दो ट्रक चालक घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय कोहरा काफी घना था। इसी दौरान दो ट्रकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।

टक्कर के तुरंत बाद पीछे से आ रहा तीसरा ट्रक भी संतुलन खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों ट्रकों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा। घायलों में ट्रक के कंडक्टर राज (31) पुत्र महेश और चालक विकास (32) पुत्र रामलखन शामिल हैं, जो फतेहपुर जनपद के गोसड़ी गांव के निवासी बताए गए हैं। तीसरे घायल चालक भगवान जाट (28) पुत्र शिवराज जाट, निवासी अजमेर, राजस्थान हैं। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद पुल मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस टीम दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाने और मार्ग बहाल करने में जुटी रही।

संक्षिप्त खबरें

साल के पहले दिन एलडीए के पार्कों में पहुंचे 81 हजार से लोग

लखनऊ, (संवाददाता)। तीन दिन मुफ्त रहने के बाद बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बृहस्पतिवार को नए साल के पहले दिन से प्रवेश शुल्क लगने लगा। भीड़ देख यहां पर बने म्यूजियम को खोल दिया गया और उसका भी शुल्क तय कर दिया गया। नए साल के पहले दिन 12 हजार से अधिक लोग इसे देखने पहुंचे। एलडीए के अन्य पार्कों में को मिलाकर कुल 81,196 हजार दर्शक घूमने पहुंचे। सबसे अधिक 41,442 लोग जनेश्वर मिश्र पार्क घूमने के लिए पहुंचे। विभिन्न पार्कों में आए दर्शकों से एलडीए को करीब 22 लाख रुपये की आमदनी हुई। 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद 29 दिसंबर से इसे जनता के लिए खोला गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक टिकट नहीं लगाया गया। नए साल के पहले दिन से अब एलडीए ने यहां पर टिकट लागू कर दिया है। प्रेरणा स्थल में प्रवेश के लिए 15 रुपये और यहां बने म्यूजियम को देखने के लिए 50 रुपये शुल्क देने पड़े। अधिकारियों के अनुसार पांच वर्ष तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए प्रवेश निशुल्क है। पार्क प्रतिदिन सुबह नौ बजे खुलेगा और रात आठ बजे बंद होगा, लेकिन टिकट शाम सात बजे तक ही मिलेगा। पहले दिन पॉश मशीनों से टिकट दिए गए। यहां पर इंटरनेट नेटवर्क धीमा होने के कारण दर्शकों को टिकट लेने में परेशानी हुई। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक टिकट लगने से दर्शक भी हैरान थे। उन्हें लगा कि यहां बीते दिनों की तरह निशुल्क प्रवेश ही मिलेगा।

एस-सी बायोटेक में कॅरिअर का मौका

लखनऊ, (संवाददाता)। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में कॅरिअर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। एस-सी बायोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं। करीब चार दशकों से वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए पहचानी जाने वाली यह कंपनी न्यूक्लियोसाइड्स, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, सहायक रिएजेंट्स और सॉलिड सपोर्ट्स के निर्माण व निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी है। कंपनी ने लविवि एवं संबद्ध महाविद्यालयों के एमएससी (केमिस्ट्री) विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। लविवि कैंपस प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. अनूप भारतीय ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी निर्धारित की गई है। यह भर्ती केमिस्ट्री विभाग के सहयोग से की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी साइंटिस्ट और जूनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव के कुल 75 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। चयन के बाद अभ्यर्थियों को लेबोरेटरी सिंथेसिस एवं प्यूरिफिकेशन गतिविधियों, बैच रिकॉर्ड तैयार करने, कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन तथा प्रोडक्शन व क्वालिटी टीम को तकनीकी सहयोग देने का दायित्व निभाना होगा। एमएससी (केमिस्ट्री) कृ ऑर्गेनिक, फार्मास्युटिकल या एनालिटिकल केमिस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। फ्रेश ग्रेजुएट फाइनल ईयर के छात्र भी आवेदन के पात्र हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मजबूत समझ, सिंथेटिक केमिस्ट्री व बायोटेक एप्लीकेशंस में रुचि तथा डॉक्यूमेंटेशन-आधारित रेगुलेटेड वातावरण में काम करने की इच्छा आवश्यक है।

राज्यमंत्री सहित विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर की मांग, आयु सीमा में तीन साल की छूट दें

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जारी किए गए विज्ञापन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में अब यूपी सरकार के राज्य मंत्री व एनडीए विधायकों ने भी आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन साल की छूट देने की मांग की है। इस संबंध में राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार, निषाद पार्टी के विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और भाजपा के हैदरगढ़ से विधायक दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अनिल त्रिपाठी ने सीएम योगी को लिखे गए अपने पत्र में कहा कि इस प्रकरण में 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर के जनता दरबार में आपने वादा किया था कि अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट दी जाएगी पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद छूट प्रदान नहीं की गई है। वहीं, प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार व भाजपा विधायक दिनेश रावत ने भी पत्र लिखकर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। इसके पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर बयान जारी कर अभ्यर्थियों का समर्थन किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार की खघमियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गये अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर, उप्र सरकार नव वर्ष का तोहफा दे! भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खघमियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगतें। हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की माँग के साथ हैं। युवाओं का भविष्य ही देश का भविष्य है। उप्र के हर युवा को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शुभेच्छा सहित नये साल की हार्दिक शुभकामनाएँ!

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लगा एंट्री टिकट, एलडीए के पार्कों में पहुंचे 81 हजार से अधिक लोग

लखनऊ, (संवाददाता)। तीन दिन मुफ्त रहने के बाद बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में बृहस्पतिवार को नए साल के पहले दिन से प्रवेश शुल्क लगने लगा। भीड़ देख यहां पर बने म्यूजियम को खोल दिया गया और उसका भी शुल्क तय कर दिया गया। नए साल के पहले दिन 12 हजार से अधिक लोग इसे देखने पहुंचे। एलडीए के अन्य पार्कों में को मिलाकर कुल 81,196 हजार दर्शक घूमने पहुंचे। सबसे अधिक 41,442 लोग जनेश्वर मिश्र पार्क घूमने के लिए पहुंचे। विभिन्न पार्कों में आए दर्शकों से एलडीए को करीब 22 लाख रुपये की आमदनी हुई। 65 एकड़ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उसके बाद 29 दिसंबर से इसे जनता के लिए खोला गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक टिकट नहीं लगाया गया। नए साल के पहले दिन से अब एलडीए ने यहां पर टिकट लागू कर दिया है। प्रेरणा स्थल में प्रवेश के लिए 15 रुपये और यहां बने म्यूजियम को देखने के लिए 50 रुपये शुल्क देने पड़े। अधिकारियों के अनुसार पांच वर्ष तक के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए प्रवेश निशुल्क है। पार्क प्रतिदिन सुबह नौ बजे खुलेगा और रात आठ बजे बंद होगा, लेकिन टिकट शाम सात बजे तक ही मिलेगा। पहले दिन पॉश मशीनों से टिकट दिए गए। यहां पर इंटरनेट नेटवर्क धीमा होने के कारण दर्शकों को टिकट लेने में परेशानी हुई। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक टिकट लगने से दर्शक भी हैरान थे। उन्हें लगा कि यहां बीते दिनों की तरह निशुल्क प्रवेश ही मिलेगा। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि बसंतकुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में प्रवेश शुल्क लागू हो गया है। म्यूजियम का भी शुल्क तय किया गया है। पहले दिन बड़ी तादाद में दर्शक वहां पर पहुंचे और उसकी खूबसूरती का निहारा।

संक्षिप्त खबरें

नववर्ष की पार्टी में युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

लखनऊ, (संवाददाता)। कृष्णानगर के बाराबिरवा स्थित निजी होटल के रूफटॉप पर आयोजित नववर्ष की पार्टी में उस समय अफरातफरी मच गई जब डीजे पर नाचते हुए दो युवकों के बीच हुई धक्का-मुक्की ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोस्तों ने घायल युवक को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना बुधवार रात की है। होटल के टॉप फ्लोर पर नववर्ष का जश्न मनाया जा रहा था। माती बिजनौर निवासी अभिषेक सिंह तीन दोस्तों रजनीश, अनुभव और युगांश के साथ पार्टी में पहुंचे थे। डीजे की धुन पर सभी झूम रहे थे। इसी दौरान अभिषेक सिंह नशे में धुत एक युवक से टकरा गए। धक्का लगने से युवक नाराज हो गया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अभिषेक की पिटाई कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने चाकू से अभिषेक के सीने पर कई वार कर दिए। इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। हालत स्थिर बताई जा रही है। कृष्णानगर इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि घायल युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान के लिए होटल में लगे कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के दौरान विवाद होने पर आरोपियों के पास चाकू कहां से आया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अगर आरोपी पहले से चाकू लेकर आया था तो होटल प्रबंधन की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि हमलावरों के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला स्पष्ट होगा। होटल के कैमरे में आरोपी कैद हो गए हैं। होटल प्रबंधन से भी पूछताछ की जाएगी।

इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिये महिला को बदनाम करने की कोशिश

लखनऊ, (संवाददाता)। पीजीआई क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता की सोशल मीडिया के जरिये हुई पहचान अब उसके और परिवार के लिए गंभीर संकट बन गई है। पीड़िता ने युवक पर बदनाम करने और परिजनों को जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़िता के अनुसार उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से रजनीश कुमार दुबे नामक युवक से हुई थी। कुछ समय तक बातचीत के बाद युवक का व्यवहार बदल गया। आरोप है कि रजनीश ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिये न केवल उसे, बल्कि उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भी लगातार कॉल और संदेश भेजकर परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा है और परिवार को जान से मारने की बात कह रहा है। कोतवाल धीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश के साथ ही सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।

ओवरलोड वाहनों से वसूली में रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ प्रवर्तन सस्पेंड

लखनऊ, (संवाददाता)। ओवरलोड वाहनों से वसूली कर पास कराने में लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ (प्रवर्तन) को बृहस्पतिवार को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के एआरटीओ राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के एआरटीओ अंबुज और फतेहपुर की एआरटीओ पुष्पांजलि मित्रा को मुख्यालय से संबद्ध कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मामले की जांच झांसी के उपपरिवहन आयुक्त केडी सिंह गौर को सौंपी गई है। बीते नवंबर में एसटीएफ ने मौरंग, गिट्टी, बालू के ओवरलोड ट्रकों को रिश्वत लेकर पास कराने के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। मामले में लखनऊ के मड़ियांव, रायबरेली के लालगंज और उन्नाव में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

इसमें वाहनों को पास कराने के खेल में शामिल 25 लोगों को नामजद किया गया था। इनमें एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर पुष्पांजलि मित्रा गौतम, पीटीओ अखिलेश चतुर्वेदी, एआरटीओ रायबरेली अंबुज, पीटीओ रेहाना, एआरटीओ लखनऊ राजीव कुमार बंसल और दलाल विनोद को भी आरोपी बनाया गया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद से नामजद अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यालय आना बंद कर दिया था। 48 दिन बाद परिवहन विभाग के विशेष सचिव केपी सिंह की ओर से जारी आदेश में लखनऊ के एआरटीओ प्रवर्तन राजीव कुमार बंसल, रायबरेली के अंबुज और फतेहपुर की पुष्पांजलि मित्रा को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ के एआरटीओ राजीव कुमार बंसल एफआईआर के बाद से गायब हैं। उनका मोबाइल बंद है। वह स्वास्थ्य कारणों को वजह बताते हुए छुट्टी पर हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जो खारिज हो गई थी। ओवरलोड वाहनों से वसूली के मामले में परिवहन विभाग के अफसरों की सुस्ती पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। 48 दिन बाद कार्रवाई को लेकर विभागीय अफसरों में हलचल है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने एसटीएफ जांच को देखते हुए लखनऊ के पीटीओ मनोज कुमार, रायबरेली की रेहाना बानो व फतेहपुर के अखिलेश चतुर्वेदी को बीते 29 नवंबर को निलंबित कर दिया था।

लोहिया संस्थान में अब दिल के डेढ़ गुना मरीजों को मिलेगा इलाज

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में पहले के मुकाबले अब रोजाना डेढ़ गुना ज्यादा मरीजों को इलाज मिल सकेगा। इसके लिए संस्थान में नई कैथ लैब शुरू की गई है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल के मरीजों को इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार बराबर प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए संस्थान में तीसरी कैथलैब की शुरुआत की गई है। इस समय संस्थान के कॉर्डियोलॉजी विभाग में रोजाना करीब 20 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर से संबंधित इलाज किए जा रहे हैं। नई कैथलैब आने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 30 तक पहुंच जाएगी। इससे दिल के मरीजों को वेटिंग कम होगी। उन्होंने कहा कि लोहिया संस्थान ने पिछले कुछ समय में मरीजों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू की हैं। यहां आने वाले मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज मिल रहा है। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह, सीएमएस डॉ. विक्रम सिंह,

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह, डॉ. श्रीकेश सिंह, रजिस्ट्रार डॉ. सुब्रत चंद्रा, डॉ. आशीष झा, डॉ. सुदर्शन कुमार विजय और डॉ. नवीन जामवाल मौजूद रहे। कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि एक और कैथलैब स्थापित की जानी है। इसके लिए उपकरणों की खरीद की जा रही है। इसके बाद संस्थान में चार कैथलैब जो जाएंगी। ऐसा होने पर दिल के मरीजों को ज्यादा बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस वर्ष कार्डियोलॉजी विभाग में एडवांस्ड इकोकार्डियोग्राफी, दो उन्नत पोर्टेबल इको, टीएमटी (ट्रेडमिल टेस्ट) मशीनें स्थापित की गई हैं। डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि संस्थान में प्रदेश भर से दिल के मरीज आ रहे हैं। कार्डियोलॉजी विभाग में एक साल में लगभग 50 हजार मरीज ओपीडी आए। आठ हजार मरीजों को भर्ती करके इलाज दिया गया।

मुसाफिरखाना तहसील में वकील और लेखपाल आमने-सामने

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेठी जिले के मुसाफिरखाना तहसील परिसर में सोमवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एसडीएम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं और उनके समर्थन में उतरे लेखपाल आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई इसके बाद धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति संभाली। जानकारी के अनुसार, तहसील में बीते कई दिनों से अधिवक्ता अभिनव कनौजिया पर अभद्र भाषा के प्रयोग और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन दिन पहले भी इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी हुई थी। सोमवार सुबह लेखपाल संघ एसडीएम के समर्थन में खड़ा हो गया। इसके बाद अधिवक्ता संघ और लेखपालों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। नारेबाजी के बीच दोनों पक्षों के कुछ लोगों में धक्का-मुक्की हो गई। सूचना मिलते ही मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस तत्काल तहसील पहुंची। भीड़ अधिक होने और माहौल तनावपूर्ण रहने के चलते एहतियातन तहसील परिसर में पीएसी भी तैनात कर दी गई है। फिलहाल पुलिस बल मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम लगातार उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बार अध्यक्ष के साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया गया। अधिवक्ता संघ ने साफ कहा कि जब तक एसडीएम का स्थानांतरण नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति को शांत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आस्था से सजी नववर्ष की सुबह

लखनऊ, (संवाददाता)। नववर्ष की पहली सुनहरी किरण जैसे ही गोमती की लहरों पर थिरकी, नवाबों का शहर एक अलग ही खुमारी में जागा। फिजाओं में शुभकामनाओं की मिठास घुली थी और मंदिरों की घंटियों के स्वर के साथ पार्कों में गूंजती हंसी ने नववर्ष का मधुर संगीत रच दिया। सूरज की पहली किरण के साथ ही बड़ी काली जी मंदिर, खाटू श्याम, हनुमान सेतु और हनुमत धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्तों ने दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। जगह-जगह धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों का आयोजन हुआ। यह दृश्य इस बात का प्रमाण था कि आधुनिकता की दौड़ में भी राजधानी अपनी जड़ों और परंपराओं से उतनी ही मजबूती से जुड़ी हुई है। लखनऊ। चौक स्थित मठ श्री बड़ी काली जी मंदिर में बृहस्पतिवार को नव वर्ष पर चौकी एवं भजन संध्या हुई। भजन गायक राम प्रताप लखा और गायिका साक्षी कंधारी ने लाल-लाल चुनरी..., बन महाकाल की काली जैसे गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां पेश कर मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन पर भंडारा हुआ। इस दौरान अभय उपाध्याय, शुभम पांडेय, देवराज सिंह, आदर्श मिश्रा, विजय गुप्ता, राहुल, तुषार, मेघनाश, आशा तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। नव वर्ष डॉ. बी एन वर्मा मार्ग स्थित परमानंद गुरुद्वारे के पास छबलानी परिवार की ओर से भंडारा लगा। इस दौरान सुरेश छाबलानी, दिलीप छाबलानी, आशा, मंजु, अमरनाथ चौधरी, जेपी नागपाल, प्रकाश गोधवानी रमेश बालानी, अनिल अग्रवाल, अनुज गौतम, रमेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लखनऊ। अलीगंज स्थित नए हनुमान मंदिर में बृहस्पतिवार को भक्तों का हुजूम देखने को मिला। पूरे दिन भंडारा चला। मुख्य पुजारी जगदंबा प्रसाद ने बताया कि मंदिर को 501 किलो फूलों से सजाया गया। सुबह से रात तक करीब दो लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं, अहियागंज स्थित सिद्धेश्वर मंदिर से मनकामेश्वर मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। सुबह आठ बजे यात्रा मनकामेश्वर मंदिर पहुंची तो भंडारा लगाया गया। महंत देव्या गिरी ने बताया कि दिनभर चले भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। नववर्ष के पहले दिन मॉल, कैफे और पार्क दोस्तों की महफिलों से गुलजार रहे।

निवेश के नाम पर कारोबारी से 15.82 लाख रुपये ऐंठे

लखनऊ, (संवाददाता)। बिजनौर में स्वपनिल सौभाग्य सोसाइटी निवासी कारोबारी शशांक शुक्ल को ऑनलाइन निवेश के सुनहरे सपने दिखाकर फर्जी महिला दरोगा और साइबर जालसाजों ने मिलकर 15.82 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया है। शशांक शुक्ल ने इस संबंध में साइबर क्राइम थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शशांक के मुताबिक उनकी पहचान सोशल मीडिया पर इशिता राय नामक महिला से हुई। उसने डार्विनेक्स ग्लोबल सीएस कंपनी में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद शशांक ने कुछ रकम निवेश की, जिस पर उन्हें मुनाफा भी दिखाया गया। विश्वास होने पर उन्होंने दोबारा नौ लाख पांच हजार रुपये निवेश किए। जब मुनाफा निकालने की कोशिश की तो उनसे 30 प्रतिशत टैक्स के नाम पर करीब चार लाख रुपये और मांगे गए। मदद की आस में शशांक औरंगाबाद में फर्जी महिला दरोगा से मिले। उसने एक युवक से मिलवाया और कंपनी में 6.77 लाख रुपये जमा करने पर पूरी रकम वापस दिलाने का वादा किया। शशांक ने यह रकम भी जमा कर दी, जो डूब गई। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह के मुताबिक ठगी में शामिल पूरे गिरोह की जानकारी जुटाई जा रही है। पीड़ित की रकम फ्रीज कराने के लिए बैंकों से संपर्क किया गया है।

माघ मेला मे जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों तैनात

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।माघ मेलादृ2026 को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक, माघ मेला के प्रत्यक्ष नेतृत्व एवं समन्वय में मेला क्षेत्र में पुलिस, केंद्रीय बल, जल सुरक्षा, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन एवं तकनीकी इकाइयों की व्यापक एवं बहु–स्तरीय संख्यात्मक तैनाती की गई है।मेला की संवेदनशीलता एवं व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए माघ मेला के लिए अलग पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है,जो मेला क्षेत्र में कानून–व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात, जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन एवं विभिन्न सुरक्षा इकाइयों के दैनिक संचालन, निगरानी एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं। पुलिस अधीक्षक, माघ मेला द्वारा की जा रही समस्त व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट प्रयागराज' द्वारा किया जा रहा है, जिससे सभी स्तरों पर प्रभावी नियंत्रण एवं त्वरित निर्णय सुनिश्चित हो सके।मेला क्षेत्र में वरिष्ठ पर्यवेक्षण हेतु 07 अपर पुलिस अधीक्षक एवं 14 पुलिस उपाधीक्षक पुलिस अधीक्षक, माघ मेला के अधीन कार्यरत हैं। सिविल पुलिस के अंतर्गत 29 निरीक्षक, 221 पुरुष उपनिरीक्षक, 15 महिला उपनिरीक्षक, 1593 पुरुष मुख्य आरक्षीध आरक्षी तथा 136 महिला मुख्य आरक्षीध आरक्षी की तैनाती की गई है।यातायात संचालन एवं नियंत्रण हेतु 04 यातायात निरीक्षक, 38 यातायात उपनिरीक्षक तथा 381 यातायात मुख्य आरक्षीध्आरक्षी तैनात किए गए हैं, जिनकी तैनाती एवं संचालन एस.पी. माघ मेला के निर्देशन में किया जा रहा है।सहायक बल के रूप में 1088 होमगार्ड एवं 304 पी.आर.डी. कर्मियों की तैनाती की गई है।कानून–व्यवस्था एवं आपदा प्रबंधन के लिए पीएसी की 05 बाढ़ राहत कंपनियाँ, 07 कानून–व्यवस्था कंपनियाँ तथा पीक डेज के लिए अतिरिक्त 05 कानून–व्यवस्था कंपनियाँ' तैनात की गई हैं।इसके अतिरिक्त 02 एनडीआरएफ टीमें, 01 एसडीआरएफ टीम, 02 आर.ए.एफ. कंपनियाँ सम्पूर्ण मेला अवधि हेतु तथा 04 आर.ए.एफ. कंपनियाँ केवल पीक डेज के लिए' तैनात की गई हैं।आंतरिक सुरक्षा एवं सघन चेकिंग के लिए '06 बी.डी.डी.एस. टीमें, 10 ए.एस. चेक टीमें, 01 एण्टी माइन्स टीम, 02 ए.टी.एस. टीमें तथा 78 एल.आई.यू. कर्मियों की तैनाती एस.पी. माघ मेला के नियंत्रण में की गई है।जल जनित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 'पुलिस अधीक्षक, माघ मेला के समन्वय में जल पुलिस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के साथ 'त्रि–स्तरीय जल सुरक्षा व्यवस्था' लागू की गई है। इसके अंतर्गत '06 जल पुलिस कर्मी, 200 मोटर बोटध्नावें, 30 प्रशिक्षित गोताखोर, पुलिस प्रशासन के पास 2000 लाइफ सेविंग जैकेट, नाविकों के पास अनुमानित 25000 लाइफ जैकेट, 461 लाइफ बाय, 04 जल पुलिस सब–स्टेशन, 08 किलोमीटर डीप वॉटर बैरिकेटिंग तथा 02 किलोमीटर फ्लोटिंग रिवर लाइन की व्यवस्था की गई है।अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु 20 फायर स्टेशन, 07 फायर चौकियाँ, 20 वॉच टॉवर, 990 फायर हाइड्रेंट, 22 हाई प्रेशर ट्यूबवेल, 153 फायर टेंडरध्वाहन एवं 761 अग्निशमन कर्मियों की तैनाती की गई है।तकनीकी निगरानी एवं सहायता के लिए 'मेला क्षेत्र में 400 एवं नगर क्षेत्र में 1152 सीसीटीवी कैमरे, 01 सेंट्रल कंट्रोल रूम, 07 खोया–पाया केंद्र, 16 महिला हेल्प डेस्क तथा 17 साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।, संख्यात्मक एवं बहु–स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से 'पुलिस अधीक्षक माघ मेला के नेतृत्व में' श्रद्धालुओं, कल्पवासियों एवं पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा एवं विश्वास सुनिश्चित किया जा रहा है।

नववर्ष पर प्रेस क्लब में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन, एसपी सिटी रहे मुख्य अतिथि

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। अयोध्या में नए साल के उपलक्ष्य में अयोध्या सिविल लाइन प्रेस क्लब में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर सीओ सिटी यश त्रिपाठी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बुके भेंट कर स्वागत किया।इस अवसर पर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने पत्रकारों को समाज का आईना बताते हुए कहा कि निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूत नींव है। उन्होंने पुलिस और प्रेस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सचिव जयप्रकाश सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया , कार्यक्रम में सैकड़ो की संख्या में पत्रकार गण मौजूद रहे। सभी ने नववर्ष में सकारात्मक पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद निर्मल खत्री, अतुल सिंह शक्ति सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, के अलावा पत्रकारों में रूपेश श्रीवास्तव भारत समाचार, रामकुमार सिंह,एसएन सिंह, बीएन दास ,नाथ बक्श सिंह, के के मिश्रा, दीप सहाय,अज्जू श्रीवास्तव, अरशद अफजल, नरेंद्र मिश्रा, महेंद्र कुमार ,गुलजार, पवन पांडे, बृजेश सिंह, सतीश पाठक, प्रेस क्लब के पूर्व सचिव पीएं तिवारी,राकेश श्रीवास्तव, द्वारकाधीश,स्वार्मिल चंद्रा हिंदुस्तान, विवेकानंद पांडे, अनिल निषाद, नवनीत कौशल डब्बू, सुमित यादव, शिवम यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, मनमीत गुप्ता, समीर शाही, राजू दुबे, अजय तिवारी, राजन तिवारी,प्रदीप पाठक, अशोक तिवारी, अंजनी सिन्हा, सत्येंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोहावल पर किया चिकित्सक पर तैनात

अयोध्या। सीएमओ डॉ. सुशील कुमार बानियान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल में जनमानस को बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएँ एवं चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करना एवं स्वच्छता, पोषण, परिवार नियोजन, संक्रमण से बचाव तथा जीवनशैली सुधार को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर एवं परामर्श सत्र आयोजित कर जनमानस को बेहतर प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किए जाने की पहल की है।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,सोहावल में डॉ पवन कुमार को सामुदायिक मेडिसिन परीक्षण हेतु नियुक्त किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कुशल निर्देशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल जनमानस को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं।जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य स्थिति में सकारात्मक सुधार हो सके।

इसौली विधानसभा में तेज हुई सियासी हलचल

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवासतव

सुलतानपुर। इसौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां इन दिनों तेज होती नजर आ रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता विकास शुक्ला लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं,जिससे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।गांव–गांव और कस्बों में लगी उनकी होर्डिंग्स ने क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है। विकास शुक्ला लगातार ग्रामीण अंचलों का दौरा कर आमजन से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। उनके इस जनसंपर्क अभियान को भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास शुक्ला जमीन से जुड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय हैं। भाजपा की नीतियों और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाने में भी वे लगातार जुटे हुए हैं।राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी नेतृत्व इसौली विधानसभा सीट से विकास शुक्ला को एक मजबूत दावेदार के रूप में देख रहा है। उनकी बढ़ती सक्रियता और क्षेत्र में मजबूत पकड़ ने उन्हें स्थानीय राजनीति का एक प्रभावशाली चेहरा बना दिया है।

'06 जनवरी से बढ़ेंगे विधानसभा मतदाता सूची में नए नाम'

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवासतव

सुल्तानपुर । 06 जनवरी को विधान सभा निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के बाद नए मतदाता के रूप में आवेदन किया जाएगा।नए मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिकों को फॉर्म 06 के साथ घोषणा पत्र(जिसमें 2003 की मतदाता सूची की डिटेल)के साथ जन्म तिथि प्रमाणित करने वाले दस्तावेज व निवास को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बता दे कि प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण के समापन के बाद 06 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।जिसमें जिन लोगों द्वारा एसआईआर फॉर्म भरा गया है उनके नाम शामिल होंगे। एस आई आर के दौरान जिन लोगों की उनके अभिभावकों (माता,पिता, दादा,दादी,नाना,नानी)के साथ मैपिंग नहीं हुई होगी।उन्हें चुनाव आयोग द्वारा 06 जनवरी से नोटिस देकर अभिलेख मांगे जाएंगे।जिसे मतदाता को 27 फरवरी तक प्रस्तुत करना होगा।मतदाता द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद ही अंतिम मतदाता सूची में उस मतदाता का नाम होगा।जिन मतदाताओं का नाम वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है।उन्हें चुनाव आयोग द्वारा निधारित फॉर्म 06 भरने होंगे साथ ही एसआईआर के लिए घोषणा पत्र भी भरना होगा।दोनो फॉर्म सहित मतदाताओं को निवास प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे– –

1.उस पते पर पानीधबिजलीध गैस कनैक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का)

2.आधार कार्ड

3.राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंकध्डाक घर की वर्तमान पास बुक

4.भारतीय पासपोर्ट

5.राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है

6.रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में)

7.रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा मे)

वही जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे ––

1.सक्षम स्थानीय निकायध नगरपालिका प्राधिकरण ध जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र

2.आधार कार्ड

3.पैन कार्ड

4.चालन अनुज्ञप्ति

5.सीबीएसइ/आईसीएसईध राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या 12 का प्रमाणपत्र, यदि इनमे जन्म तारीख अंतर्विष्ट है।

6.भारतीय पासपोर्ट

उक्त अभिलेखों के साथ पूर्ण भरा हुआ फॉर्म 06 , 06जनवरी से लेकर 06 फरवरी तक बीएलओ को देने होंगे।तभी नए मतदाता के रूप में 06 मार्च को जारी होने वाली विधानसभा निर्वाचक नामावली में शामिल हो पाएंगे।

कड़ाके की ठंड से जनजीवन रहा प्रभावित,ठिठुरते दिखे लोग

(राजन तिवारी जिला संवाददाता अयोध्या धाम)

अयोध्या। शनिवार को घने बादल तथा ठंड के चलते जन जीवन अस्त व्यस्त रहा। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरा के चलते गाड़ियां भी काफी लेट चल रही थी।जबकि ठंड का असर लखनऊ की ओर आने जाने वाले रोडवेज बसों के अलावा चार पहिया वाहनों पर भी दिखाई दिया।2 दिन पहले हल्की धूप खिलने का असर यह दिखा कि शनिवार को पूरे दिन बादल छाया रहा और कड़ाके की ठंड के चलते कई लोग अपने–अपने घरों में भी दुबके रहे।मौसम विभाग द्वारा ठंड को लेकर जानकारी को देखते हुए एक दिन पहले ही इंटर तक के सभी स्कूल कॉलेज शासन प्रशासन द्वारा 5 जनवरी तक बंद कर दिए गए थे। शनिवार को भोर हालत यह रही कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी की छोटी–छोटी बूंदें टपक रही हो।ठंड पूरी तरह से लोगों को अपने आगोश में कर रखे थे और पूरे दिन लोग अपने–अपने घरों में ही दुबके नजर आए बाहर वही दिखाई दे रहे थे।जिन्हें मजबूरी में ऑफिस या किसी अन्य काम के लिए निकलना पड़ रहा था वह सभी भी अपने को गर्म कपड़ों से ढके नजर आए लेकिन इस दौरान नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था कुछ ही जगह पर दिखाई दे रही थी लेकिन खासकर रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टेशन, जिला चिकित्सालय सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर अलाव जलते नहीं देखे गए।जबकि शासन ने सख्त निर्देश सभी जिले के जिलाधिकारी को दिया है कि वे सभी अपने–अपने जिलों के रैन बसेरा व सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करें कोई भी खुले में ना सोए लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन में कुछ लोग खुले रूप से सोते हुए पाए गए।वही इस ठंड में रेलवे स्टेशन बस स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर लोग ठंड से कापते हुए दिखाई दे रहे थे।इस ठंड को देखते हुए चिकित्सकों ने भी खासकर डायबिटीज,बुजुर्गध,और छोटे बच्चों से जरूरी हो तभी बाहर निकल नहीं तो घर से बाहर निकालने की सलाह नहीं दिए।क्योंकि इस ठंड से हार्ट पर असर पड़ सकता है और वही छोटे बच्चों की भी तबीयत खराब हो सकती है।वही मौसम विभाग ने भी बताया है कि यह ठंड अभी कुछ दिनों तक रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

फरार घोषित जिला पं अध्यक्ष की पत्नी ने पेश की अग्रिम जमानत अर्जी

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवासतव

सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में फरार घोषित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की तरफ से बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत ने पांच जनवरी की तारीख तय किया है। अग्रिम जमानत अर्जी लम्बित होने को आधार बनाते हुए चंद्रमा देवी की तरफ से एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में एनबीडब्ल्यू व फरार घोषित करने की कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की गई है। एसीजेएम कोर्ट ने मामले में आपत्ति आमंत्रित करते हुए सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय किया है। अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने 25 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत किया था। परिवादी ने मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए थे। यह मामला परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आठ फरवरी 2024 को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों को फर्जीवाड़े के मामले में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में आरोपियों की तरफ से चुनौती दी गई,लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। मामले में अदालत ने गत 23 दिसम्बर को आरोपियो के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व उन्हें फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई भी जारी करने का आदेश दिया। अदालत के कड़े रुख को देखने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट खुलते ही आरोपी चंद्रमा देवी की तरफ से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश करने के बाद उसी का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी कार्रवाई रोकने की मांग की गई है।

मुठभेड़ में दो शातिर घायल,डीसीएम ट्रक चोरी केस में बड़ी कार्रवाई

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवासतव

सुल्तानपुर। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में डीसीएम ट्रक चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6ध्7 नवंबर 2025 की रात चोरी हुए डीसीएम ट्रक के संबंध में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान पांच अभियुक्त प्रकाश में आए थे,जिनमें से दो आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।शनिवार को सूचना मिली कि शेष अभियुक्तों में से दो आरोपी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से पाखरौली रेलवे क्रॉसिंग की ओर जा रहे हैं। सूचना पर एसओजी टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया,जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी।घायल अभियुक्तों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया,जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में इन्हीं अभियुक्तों में से चार ने थाना गोसाईगंज क्षेत्र में 34 टन सरिया की लूट की घटना को भी अंजाम दिया था। वर्तमान प्रकरण के पांच अभियुक्तों में वे चार भी शामिल हैं। एक अभियुक्त अभी फरार है,जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं।उक्त घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर अखण्ड प्रताप सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे।

सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता बैठक आयोजित दिलाई गई शपथ 31 जनवरी तक चलेंगे विशेष अभियान

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवासतव

सुलतानपुर । जिलाधिकारी कुमार हर्ष के निर्देश पर जनपद सुलतानपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा हैं यह अभियान 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा बस, ट्रक, ऑटो,ई–रिक्शा एवं टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ एक जागरूकता बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता पीटीओ शैलेंद्र तिवारी ने की इस दौरान परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे बैठक में अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह मानव जीवन की रक्षा का सशक्त माध्यम हैं ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना, तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए वाहन चालकों से सीट बेल्ट, हेलमेट, ट्रैफिक सिग्नल, लेन ड्राइविंग एवं निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की गई साथ ही सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक हैं इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम विशेष चेकिंग अभियान एवं प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम में उपस्थित सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने सड़क सुरक्षा अभियान में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

जीआईसी के पीछे तुलसी धाम मोहल्ला मोहल्ला का शव मिलने से सनसनी

अयोध्या। कोतवाली नगर क्षेत्र मे अयोध्या के जीआईसी स्कूल के पीछे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी श्रेयश त्रिपाठी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच और मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस को अंदेशा है कि महिला की मृत्यु गला घोटने की वजह से हुई है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और महिला की शिनाख्त करने के प्रयास जारी हैं ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

दो बूथों पर आज 1337 अधिवक्ता करेंगे मतदान

भदोही, (संवाददाता)। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को मध्यस्थता सेंटर में बनाए गए दो बूथों पर 1337 अधिवक्ता मतदान करेंगे। सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद पर छह समेत कुल 39 प्रत्याशी हैं। जिला बार एसोसिएशन चुनाव के वार्षिक चुनाव की तैयारी वैसे तो महीने भर से चल रही है। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी होने के बाद अध्यक्ष पद पर छह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर तीन, महासचिव पद पर तीन, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर चार, उपाध्यक्ष 10 वर्ष के नीचे के लिए दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। कोषाध्यक्ष के लिए चार, संयुक्त सचिव पर चार, आय–व्यय पर एक, वरिष्ठ कार्यकारिणी में सात और कनिष्ठ में चार उम्मीदवार समेत कुल 39 प्रत्याशी बचे हैं। अब एल्डर्स कमेटी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में जुटी है। एल्डर्स कमेटी के सदस्य मोहन लाल मिश्रा ने बताया कि दो जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक मतदाता बूथों पर मत डालेंगे। उन्होंने बताया कि कुल 1337 अधिवक्ता मतदान करेंगे। मध्यस्थता सेंटर में दो बूथ बनाए गए हैं। मतदान के लिए सभी अधिवक्ता मतदाता अपना सीओपी परिचय पत्र साथ लेकर आएं। न लाने पर मतदान से वंचित किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए पंचायती राज निदेशक को भेजी रिपोर्ट

भदोही, (संवाददाता)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे–धीरे बढ़ने लगी है। चुनाव में अभी चार से पांच महीने शेष हैं, लेकिन गांव–गांव अब चुनावी माहौल बनने लगा है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 26 मई और 19 जून 2026 तो जिला पंचायत का कार्यकाल 11 जुलाई, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए दावेदार अभी से लोगों से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। पंचायत राज विभाग ने निर्धारित समय सीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए पंचायती राज निदेशक को रिपोर्ट भेजी है। जिले में 26 जिला पंचायत सदस्य, 546 ग्राम प्रधान, 661 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 6848 ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव होना है।

कुशीनगर में युवक की हत्या के बाद तनाव, साढ़े चार घंटे बाद चौराहे से हटाया गया शव

गोरखपुर, (संवाददाता)। कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की एक घटना में 22 वर्षीय युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम होकर आने पर अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए नैका छपरा चौराहे पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के कारण मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। लोग आरोपियों के घर पर बुलडोजर और एनकाउंटर की मांग करने लगे। यह घटना बुधवार को कसया थाना क्षेत्र के जुड़वनिया गांव के पास हुई, जहां 22 वर्षीय निशांत सिंह पुत्र संतोष सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि निशांत अपने गांव के दो दोस्तों के साथ बाइक से कसया जा रहा था। गांव से करीब एक किलोमीटर आगे पहुंचते ही रास्ते में पहले से मौजूद दो युवकों ने बाइक रोक ली और कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने निशांत पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल निशांत को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार निशांत खेत के लिए खाद लेने जा रहा था और उसके साथ कुंदन और विशाल थे। बीच–बचाव करने के दौरान निशांत पर गले और पेट पर कई बार चाकू से वार किया गया। मृतक अपने माता–पिता की इकलौता संतान था और 12वीं की पढ़ाई के बाद सेना व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पिता खेती–बाड़ी कर परिवार का पालन–पोषण करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही दोनों गांवों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने नैका छपरा चौराहे पर शव रखकर करीब साढ़े चार घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए मौके पर एडीएम विभव मिश्र, एडिशनल सिद्धार्थ वर्मा समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। पीएसी की एक यूनिट भी एहतियातन मौके पर मौजूद रही। प्रशासन द्वारा लगातार समझाने–बुझाने के बाद पुलिस ने करीब साढ़े चार घंटे बाद शव को चौराहे से हटवाकर परिजनों के घर भिजवाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मृतक और आरोपी पक्ष के गांवों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।